52 लोगों की मौत हो गई है ब्राजील की एक जेल में हुए खूनी संघर्ष में। इनमें 16 लोगों का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। एक जेल अधिकारी ने बताया कि जेल के भीतर दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। इन्होंने जेल के दो अधिकारियों को बंधक भी बना लिया था।

कमजोर नहीं हुआ है आतंकी संगठन अलकायदा

हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों में शुमार अलकायदा कमजोर नहीं हुआ है। पाकिस्तान पोषित लश्कर-ए-तैयबा और हक्कानी नेटवर्क आदि आतंकी संगठनों के साथ उसका सहयोग का सिलसिला जारी है। साथ ही इस संठगन से जुड़े आतंकी तालिबान के लिए सैन्य एवं धार्मिक निर्देशकों के तौर पर नियमित रूप से काम कर रहे हैं।

31,400-57,600
संगठन में मौजूद आतंकियों की संख्या

ऐसे तैयार हुई रिपोर्ट

यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अलकायदा प्रतिबंध समिति को इस महीने सौंपी गई विश्लेषणात्मक सहायता और प्रतिबंध निगरानी टीम की 24वीं रिपोर्ट में सामने आई है। निगरानी करने वाली टीम इस्लामिक स्टेट, अलकायदा और संबंधित व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं पर सुरक्षा परिषद को हर छह महीने में स्वतंत्र रिपोर्ट सौंपती है।

नेतृत्व को लेकर संदेह

रिपोर्ट में कहा गया है कि अलकायदा का सरगना **अयमन मुहम्मद रबी अल-जवाहिरी** की सेहत खराब है। लिहाजा उसकी मृत्यु के बाद संगठन के सामने नेतृत्व को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। हालांकि ओसामा बिन लादेन का बेटा हमजा बिन लादेन संगठन का प्रमुख नेता बनकर उभरा है। अमेरिका उसे दो साल पहले ही वैश्विक आतंकवादी घोषित कर चुकी है।

हमजा बिन लादेन ओसामा बिन लादेन

कब हुई स्थापना

अलकायदा की स्थापना 1988 में ओसामा बिन लादेन, अब्दुल्लाह आजम ने सोवियत-अफगान युद्ध के दौरान की थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, नाटो, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन ,भारत, रूस और कई अन्य देशों द्वारा यह संगठन एक वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित है।

सुरक्षित ठौर

अलकायदा अफगानिस्तान को अपना सबसे सुरक्षित ठौर मानता है। तालिबान के सहयोग से वह बदख्शां प्रांत विशेष रूप से तजाकिस्तान की सीमा पर स्थित शिगनान क्षेत्र के साथ पकतिका प्रांत के बारमल में में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए उत्सुक है।

आतंक से निपटने में कमजोर हैं ये देश

रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया कि अफगानिस्तान, लीबिया और सोमालिया जैसे देशों की सरकारों के पास आतंकवादी चुनौतियों का सामना करने की क्षमता सीमित हैं। यह देश आतंकवाद से बुरी तरह प्रभावित हैं।

इन क्षेत्रों में है मजबूत

अलकायदा से जुड़े आतंकी समूह इदलिब, सीरिया, यमन, सोमालिया और पश्चिम अफ्रीका में इस्लामिक स्टेट (आइएस) की तुलना में अधिक मजबूत हैं। विदेशी आतंकवादी लड़ाकों की सबसे बड़ी संख्या इदलिब और अफगानिस्तान में है। इनमें से अधिकांश अलकायदा के साथ जुड़े हैं। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वित्त, मीडिया प्रोफाइल, मौजूदा युद्ध का अनुभव और आतंकवादी विशेषज्ञता के मामले में इस्लामिक स्टेट अलकायदा से बहुत मजबूत है और वैश्विक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है।

न्यूज गैलरी

पाकिस्तान में भारी बारिश से 34 लोगों की मौत

कराची : पाकिस्तान के अनेक हिस्सों में भारी बारिश और इससे जुड़ी घटनाओं में 34 लोगों की मौत हो गई। सोमवार को सिंध प्रांत में हुई मूसलाधार बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं में 18 लोगों की मौत हो गई। तेज वर्षा से कराची शहर में कई जगहों पर पानी भर गया। दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश से खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अचानक आई बाढ़ से 16 लोगों की मौत हो गई, जिसमें महिलाएं एवं बच्चे भी शामिल हैं। (प्रेट्र)

ऑस्ट्रेलियाई संसद के बाहर शरणार्थियों ने किया प्रदर्शन

कैनबरा : ऑस्ट्रेलिया द्वारा शरणार्थियों को दी जाने वाली वीजा पद्धति में बदलाव के विरोध में सैंकड़ों शरणार्थियों ने सोमवार को यहां संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। शरणार्थियों ने बताया कि सरकार द्वारा उन्हें स्थायी सुरक्षा वीजा के बदले अब अस्थायी वीजा दिए जाने की बात कही जा रही है। इसे लेकर शरणार्थियों के बीच हताशा का माहौल है। विरोध जताने वाले शरणार्थियों के इस समूह में रोहिंग्या मुस्लिमों के अलावा इराक, ईरान, श्रीलंका, सूडान और सोमालिया से आकर ऑस्ट्रेलिया में आश्रय लिए शरणार्थी भी शरीक थे। (एपी)

इंडोनेशिया ने फ्रांस और हांगकांग को कचरा वापस भेजा

जकार्ता : इंडोनेशिया ने अवैध तरीके से भेजे गए सात कंटेनरों में भरे कचरे को वापस फ्रांस और हांगकांग रवाना कर दिया है। सिंगापुर के नजदीक बातम द्वीप से खतरनाक श्रेणी के कचरे से भरे जहाजों को सोमवार को इन दोनों देशों के लिए वापस भेज दिया गया। इंडोनेशिया के कस्टम विभाग के स्थानीय प्रमुख सुसिला ब्रता ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। इनमें से पांच कंटेनर हांगकांग और दो फ्रांस वापस भेजे गए हैं। इंडोनेशिया का कहना है कि अवैध कचरे के निस्तारण करने में उन्हें बड़ी मशक्कत करने पड़ी रही है और वहां कूड़े के ढेर भी लग गए हैं। (एएफपी)

अमेरिकी बैंक के दस करोड़ ग्राहकों का डाटा चोरी

न्यूयॉर्क टाइम्स से

कैपिटल वन का सर्वर हैक करने पर महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार

वाशिंगटन : क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले अमेरिका के तीसरे सबसे बड़े बैंक कैपिटल वन के ग्राहकों का डाटा चोरी होने का बड़ा मामला सामने आया है। एक महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बैंक का सर्वर हैक कर दस करोड़ से ज्यादा ग्राहकों के निजी डाटा में सेंध लगा दी। इसे बैंकिंग क्षेत्र में डाटा चोरी के सबसे बड़े मामलों में गिना जा रहा है। डाटा चोरी को अंजाम देने वाली महिला पेज थॉमसन (33) को गिरफ्तार कर लिया गया है।

अमेरिकी अभियोजकों ने सोमवार को बताया कि सिएटल की रहने वाली थॉमसन कैपिटल वन के डाटाबेस का संचालन करने वाली अमेजन वेब सर्विसेज के लिए काम कर चुकी है। उसने इसी डाटाबेस में सेंधमारी कर ग्राहकों की निजी जानकारी तक पहुंच बनाई। कैपिटल वन के अनुसार, थॉमसन ने एक लाख 40 हजार सोशल सिक्योरिटी नंबर और 80 हजार बैंक अकाउंट नंबरों की चोरी की। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के लिए आए करोड़ों आवेदनों की भी चोरी हुई। ये आवेदन 2005 से 2019 के बीच दाखिल किए गए थे। बैंक ने हालांकि कहा, 'हमारा मानना है कि जानकारी का उपयोग धोखाधड़ी के लिए नहीं किया गया। इसका प्रसार किए जाने की भी संभावना कम है।' कैपिटल वन ने यह भी बताया कि डाटा चोरी से उसे 15 करोड़ डॉलर (करीब एक हजार करोड़ रुपये) की चपत लगेगी।

ऐसे हुई हैकर की पहचान : अभियोजकों के अनुसार, महिला की पहचान तब हुई, जब उसने सोशल मीडिया पर एक बिल का फोटो पोस्ट किया। उसे यह बिल अपने पालतू जानवरों की देखभाल करने वाले एक पशु चिकित्सक की ओर से मिला था। उसे अपने अपराध के लिए कोई पछतावा नहीं है।

डाटा तक इस तरह बनाई पहुंच : डाटा चोरी की जांच करने वाले एफबीआइ के अधिकारी ने बताया कि यह सबकुछ एक वेब एप्लीकेशन के फायरवाल के कांफिगरेशन में आई गड़बड़ी के चलते हुआ। इसी से थॉमसन संवेदनशील डाटा तक पहुंच बनाने में सफल हुई। अमेजन ने कहा है कि ग्राहक अपने एप्लीकेशन को पूरी तरह नियंत्रित करते हैं। जबकि कैपिटल वन ने कहा कि कांफिगरेशन की गड़बड़ी को दूर कर लिया गया है।

घर से डिजिटल डिवाइस बरामद : एफबीआइ के अधिकारियों ने सोमवार को थॉमसन के घर पर छापा मारा। उसके घर से कई डिजिटल डिवाइस बरामद हुईं। इनमें कैपिटल वन से संबंधित कई अहम जानकारियां मिलीं।

यह बैंकिंग क्षेत्र में हुई डाटा चोरी की सबसे बड़ी वारदात है। फाइल

2017 में चोरी हुई थी 14.7 करोड़ ग्राहकों की जानकारी

2017 में अमेरिका की क्रेडिट-रिपोर्टिंग कंपनी इक्विफैक्स इंक के डाटा में सेंध लगी थी। तब करीब 14 .7 करोड़ लोगों की जानकारी चोरी हुई थी। इस कंपनी ने पिछले हफ्ते बताया था कि डाटा चोरी के इस मामले के निपटारे के लिए उसे 70 करोड़ डॉलर (करीब 4800 करोड़ रुपये) का भुगतान करना पड़ेगा।

हिरासत केंद्रों से छोड़े 90 फीसद उइगर : चीन

- चीनी अधिकारियों ने अपने दावे में मुहैया नहीं कराई कोई ठोस जानकारी

बीजिंग : उइगर मुस्लिमों के मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर वैश्विक आलोचना और दबाव का सामना कर रहे चीन ने मंगलवार को चौंकाने वाला दावा किया। चीनी अधिकारियों ने कहा कि सरकारी केंद्रों में रखे गए ज्यादातर अल्पसंख्यक मुस्लिमों को छोड़ दिया गया है। उन्होंने हालांकि अपने दावे के समर्थन में कोई ठोस जानकारी नहीं दी। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि कितनी संख्या में उइगर मुस्लिम रिहा किए गए हैं? पिछले साल ऐसी खबरें आई थीं कि चीन ने शिनजियांग प्रांत में दस लाख से ज्यादा उइगर मुस्लिमों को कथित तौर पर कट्टरवाद विरोधी गुप्त हिरासत केंद्रों में कैद कर रखा है। चीन इन केंद्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण शिविर बताता रहा है।

शिनजियांग के वाइस चेयरमैन अल्केन तुनिज ने मंगलवार को कहा, 'अभी सरकारी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जितने लोग शिक्षा और प्रशिक्षण ले रहे थे, उनमें से 90 फीसद अपने परिवारों और समाज में लौट गए हैं। इनमें से ज्यादातर रोजगार पाने में सफल हुए।' प्रांतीय सरकार के चेयरमैन ने भी इसी तरह का बयान दिया है। इन बयानों से यह जाहिर होता है कि चीन हिरासत केंद्रों को लेकर वैश्विक स्तर पर अपनी छवि सुधारने में जुट गया है। हिरासत केंद्रों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बंदी बनाए जाने को लेकर वह अमेरिका समेत कई देशों की आलोचना झेल चुका है। चीन के इस दावे का स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाना लगभग असंभव है क्योंकि शिनजियांग में कई तरह की सख्त बंदिशें लगाई गई हैं। कोई भी विदेशी इस क्षेत्र में आसानी से पहुंच नहीं सकता।

चीन के दावे पर संदेह : वाशिंगटन में रहने वाले उइगर सामाजिक कार्यकर्ता ताहिर इमिन ने चीन के दावे पर संदेह जाहिर किया है। उन्होंने कहा, 'विदेश में रहने वाले उइगरों का शिनजियांग में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से संपर्क नहीं हो रहा है। ना तो फोन पर बातचीत हो पाती है और ना ही इंटरनेट से संपर्क हो पाता है। हमें इस बात का यकीन नहीं है कि वे रिहा किए गए हैं। अगर चीन की सरकार ईमानदार है तो लोगों को स्वतंत्र रूप से बातचीत करने दे और मीडिया के लोगों को स्वतंत्र जांच के लिए वहां जाने दे।'

शिनजियांग में कई तरह के प्रतिबंध : अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा से सटे शिनजियांग में 1.1 करोड़ से ज्यादा उइगर मुस्लिम रहते हैं। इस क्षेत्र में कई तरह के कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। वहां लोगों के असामान्य दाढ़ी रखने और बुर्का पहनने पर प्रतिबंध है। क्षेत्र के सभी कार मालिकों को ट्रैकिंग डिवाइस जीपीएस लगाने का आदेश दिया गया है। क्षेत्र में निगरानी के लिए ड्रोन भी तैनात किए गए हैं।

चीनी संस्कृति की दी जाती है सीख : शिनजियांग में बनाए गए हिरासत केंद्रों में से एक में काम करने वाली एक कजाख महिला ने हाल में यह बताया था कि इन केंद्रों में अल्पसंख्यक मुस्लिमों को रखा जाता है। उन्हें कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ ही चीनी भाषा और संस्कृति के बारे में सीख दी जाती है।

22 देशों ने किया था आग्रह : इस महीने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी समेत 22 देशों ने संयुक्त बयान जारी कर चीन से हिरासत केंद्रों में बंदी बनाए गए उइगरों और अन्य मुस्लिमों को रिहा करने का आग्रह किया था।

अलग होना चाहते हैं उइगर : शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुस्लिम 'ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट' चला रहे हैं जिसका मकसद चीन से अलग होना है। 1949 में पूर्वी तुर्किस्तान, जो अब शिनजियांग है, को एक अलग राष्ट्र के तौर पर कुछ समय के लिए पहचान मिली थी।

- चीनी अधिकारियों ने अपने दावे में मुहैया नहीं कराई कोई ठोस जानकारी

चीन पर दस लाख से ज्यादा उइगर मुस्लिमों को हिरासत में रखने का आरोप है। फाइल

प्रतिबंधों के कारण ईरान में जरूरी दवाओं की कीमतें आसमान पर

तेहरान, एपी : परमाणु करार से बाहर होने के बाद अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों से देश की अर्थव्यवस्था की हालत बेहद खराब हो गई है। खस्ताहाल अर्थव्यवस्था का असर दवाओं की कीमतों पर भी पड़ा है। दवाओं की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इसकी वजह से कई जरूरी दवाएं ईरान की आम जनता की पहुंच से दूर हो गई हैं।

ईरान के स्वास्थ्य मंत्री सईद नमाकी ने पिछले सप्ताह कहा था कि कच्चे तेल के निर्यात में आई गिरावट से स्वास्थ्य मंत्रालय का बजट भी प्रभावित हुआ है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर लगे प्रतिबंध के चलते दूसरे देशों से संपर्क लगभग टूट गया है। ईरान को दूसरे मुल्कों से किसी तरह की वित्तीय मदद नहीं मिल पा रही क्योंकि बैंकिंग लेन-देन पर भी पाबंदी लगी है। इससे ईरान की समूची अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गई है। अमेरिकी सरकार का हालांकि कहना है कि ईरान पर लगी पाबंदियों से दवाओं और मेडिकल उपकरणों को बाहर रखा गया है। नमाकी का कहना है कि यह अमेरिका का सफेद झूठ है।

- कच्चे तेल के निर्यात में आई गिरावट, दूसरे देशों से भी लगभग टूट गया है संपर्क

ईरान के एक अस्पताल के डॉक्टर अरासब अहमदियन ने कहा 'हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है कि लगभग पूरी दुनिया के द्वार हमारे लिए बंद हो चुके हैं। उनका अपना अस्पताल भी दान के बल पर चल रहा है। विदेशों से मिलने वाले दान को भी बैंकों ने ब्लॉक कर दिया है।' उन्होंने कहा कि उम्मीद है जल्द ही ईरान पर लगे प्रतिबंध जल्द ही समाप्त हो जाएंगे और हालात सामान्य हो जाएंगे।

ईरानी मुद्रा की कीमत में जबरदस्त गिरावट : अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध के कारण ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत में जबरदस्त गिरावट आई है। 2015 में हुए परमाणु करार के वक्त अंतरराष्ट्रीय बाजार में जहां एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रियाल की कीमत 32 हजार थी, जो अब एक लाख 20 हजार हो गई है।

गुलाम कश्मीर में पनबिजली प्रोजेक्ट के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, प्रदर्शन

मुजफ्फराबाद, एएनआइ : गुलाम कश्मीर में नीलम-झेलम पनबिजली परियोजना को लेकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों ने मुजफ्फराबाद की सड़कों पर उतरकर अपने गुस्से को जाहिर किया और पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए। क्षेत्र के लोग पहले से ही पाकिस्तान की भेदभावपूर्ण नीतियों से जूझ रहे हैं। उन्हें अब इस परियोजना के चलते पानी की कमी से भी जूझना पड़ रहा है।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पनबिजली परियोजना पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों खासतौर पर पंजाब के लिए बनाई गई है। नीलम-झेलम नदियों के पानी को पनबिजली संयंत्र की ओर मोड़ दिया गया है। इससे क्षेत्र में पानी की भारी किल्लत शुरू हो गई है। उनकी रोजमर्रा की जरूरतें तक पूरी नहीं हो पा रहीं।

पानी की किल्लत के चलते पलायन: गुलाम कश्मीर में हाल के दौर में पानी की किल्लत की समस्या शुरू हुई। पनबिजली परियोजना के चलते कई लोग बेघर हो गए। जबकि कईयों को पानी की किल्लत के चलते पलायन करना पड़ रहा है।

2018 में शुरू हुआ था नीलम-झेलम हाइड्रोपावर प्लांट : नीलम-झेलम हाइड्रोपावर प्लांट का संचालन अगस्त, 2018 में शुरू हुआ था। इस संयंत्र की 1500 मेगावॉट बिजली पैदा करने की क्षमता है। इतना बड़ा संयंत्र शुरू होने के बावजूद गुलाम कश्मीर को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही। जबकि इस क्षेत्र की जरूरत महज 500 मेगावॉट बिजली की है।

पर्यावरण को नुकसान पहुंचने का डर: नीलम और झेलम नदियों पर कई बांध बनाने की पाकिस्तान सरकार की योजना को लेकर गुलाम कश्मीर के लोगों में इस बात का डर है कि इससे स्थानीय पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। इसी आशंका के मद्देनजर स्थानीय लोग इस तरह की परियोजनाओं पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं।

मुजफ्फराबाद (गुलाम कश्मीर) में नीलम-झेलम पनबिजली परियोजना के निर्माण के विरोध में हजारों लोगों ने सड़क पर उतरकर गुस्से का इजहार किया और पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए। (एएनआइ)

पत्नी की हत्या में तेहरान के पूर्व मेयर को मौत की सजा

तेहरान, एएफपी : ईरान की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में राजधानी तेहरान के पूर्व मेयर मुहम्मद अली नजफी (67) को मौत की सजा सुनाई है। गणितज्ञ, प्रोफेसर और वरिष्ठ नेता नजफी राष्ट्रपति हसन रूहानी के आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। नजफी के पास इस फैसले को 20 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का अधिकार है।

ईरानी न्यायपालिका के प्रवक्ता के अनुसार, अदालत ने नजफी को अपनी दूसरी पत्नी मितरा ओस्ताद की गोली मारकर हत्या करने का दोषी करार दिया। कोर्ट ने इसे सुनियोजित हत्या का मामला बताया। नजफी की पत्नी गत 28 मई को उनके तेहरान स्थित आवास में बाथ टब में मृत अवस्था में पाई गई थीं। जांच-पड़ताल के दौरान नजफी ने अपना जुर्म स्वीकार लिया था। अदालत ने गैरकानूनी तरीके से हथियार रखने के लिए नजफी को अलग से दो साल की सजा सुनाई है। तेहरान के मेयर की कुर्सी संभालने से पहले नजफी ईरान के शिक्षा मंत्री के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

नजफी को अगस्त 2017 में उन्हें तेहरान महापौर चुना गया, लेकिन स्कूली छात्राओं द्वारा किए गए नृत्य में भाग लेने के लिए उन्हें परंपरावादियों की आलोचना का सामना करना पड़ा और बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया।

रावलपिंडी के पास रिहायशी इलाके में गिरा पाक सेना का विमान, 19 की मौत

- विमान गिरने से बस्ती के कुछ घरों में लगी आग, सुरक्षा अधिकारियों ने पाया काबू
- सेना ने कहा, नियमित अभ्यास के तहत उड़ान पर था विमान

रावलपिंडी, आइएएनएस : पाकिस्तान की सेना का एक प्रशिक्षण विमान मंगलवार को दुर्घटनाग्रस्त होकर रावलपिंडी स्थित सैन्य मुख्यालय के करीब एक रिहायशी बस्ती पर गिरा। इस हादसे में विमान के दोनों पायलटों समेत 19 लोगों की मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वाले 13 लोग बस्ती में रहने वाले आम नागरिक थे। बताया जा रहा है कि सेना का यह विमान नियमित अभ्यास के तहत उड़ान पर था।

दुर्घटना किस वजह से हुई और यह कौन-सा विमान था, इसे लेकर कुछ भी नहीं बताया गया है। मौके पर पहुंचे सेना के एक अधिकारी ने बताया कि विमान पॉश इलाके बहिया टाउन से सटे एक गांव मोरा कालू में गिरा। हादसे में 13 स्थानीय लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटनाग्रस्त विमान जिस मकान पर गिरा, उसमें आग लग गई। आसपास के चार और घर इस आग की चपेट में आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विमान के पिछले हिस्से में पहले से ही आग लगी थी।

गिरने के बाद तेज धमाके के साथ आग के शोले आसपास फैल गए और कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। राहत और बचाव कार्य में जुटी एजेंसी के प्रवक्ता फारूक बट ने बताया कि शव इतनी बुरी तरह जल गए हैं कि उनकी पहचान कर पाना मुश्किल है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी और प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस घटना पर दुख जताया है।

रावलपिंडी में मंगलवार को रिहायशी इलाके में पाकिस्तानी सेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद मौके पर जुटे जवान। इस हादसे में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई है। एपी

चीन ने लगाया आरोप हांगकांग प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका का हाथ

बीजिंग, प्रेट्र : चीन ने हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों को लेकर अमेरिका पर आरोप लगाया कि हांगकांग में बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों के पीछे वाशिंगटन का हाथ है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो के हाल के उस बयान पर भी सवाल खड़े किए, जिसमें उन्होंने कहा था कि हांगकांग में प्रदर्शनों से निपटने में चीन को 'ठीक से काम करना चाहिए।'

प्रवक्ता ने कहा कि शीर्ष अमेरिकी राजनयिक को अभी भी लगता है कि वह सीआइए प्रमुख हैं। बता दें कि पोंपियो विदेश मंत्री बनने से पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआइए के निदेशक थे। हांगकांग में प्रदर्शनों की शुरुआत एक विवादित विधेयक को लेकर हुई थी। इस विधेयक के पारित हो जाने पर किसी आरोपित को चीन प्रत्यर्पित करने का मार्ग प्रशस्त हो जाता। विरोध प्रदर्शनों के कारण इस विधेयक को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। हालांकि, प्रदर्शनों ने व्यापक रूप ले लिया है और अब लोकतांत्रिक सुधारों की मांग की जा रही है।

जहाज को बंधक बनाते वक्त ब्रिटेन के सैनिकों ने की बर्बरता

- एक भारतीय कप्तान ने साझा की आपबीती
- इस महीने की शुरुआत में रॉयल मरीन ने ईरानी जहाज को बना लिया था बंधक

लंदन, प्रेट्र : ईरानी जहाज के भारतीय कप्तान ने कहा है कि ब्रिटिश सैनिकों ने जब उनके (ईरानी) जहाज को बंधक बनाया तब उन्होंने 'बर्बर व्यवहार' किया था। इस महीने की शुरुआत में रॉयल मरीन ने ईरानी जहाज को बंधक बना लिया था।

जिब्राल्टर के अधिकारियों ने चार जुलाई को रॉयल मरीन की मदद से ईरान के 'ग्रेस-1' टैंकर को बंधक बना लिया था। उन्हें संदेह था कि वह जहाज यूरोपीय संघ (ईयू) के प्रतिबंधों का उल्लंघन कर 20 लाख बैरल से ज्यादा कच्चा तेल सीरिया ले जा रहा था। जहाज के सेलिंग (नौकायन) मास्टर और मुख्य अधिकारी दोनों भारतीय थे। उन्हें भी यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, बाद में उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी गई थी।

एक भारतीय कप्तान ने नाम उजागर न करने की शर्त पर बीबीसी को बताया कि हेलीकॉप्टर से जहाज पर उतरने के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने बंदूक का भय दिखाकर उनके निहत्थे चालक दल के सदस्यों को जहाज के डेक पर घुटनों के बल बैठाए रखा। उसने खुद को कप्तान बताया, लेकिन मरीन ने इसकी अनदेखी की। उन्होंने उन पर बंदूकें तान दीं और उन पर चिल्लाते हुए कहा, 'आगे देखो, आगे देखो'।

उन्होंने बताया, 'कोई नियम नहीं था, हम 28 निहत्थे चालक दल के सदस्य थे। मैं स्तब्ध था, हर कोई स्तब्ध था।' उसने कहा कि ऐसे बर्बर सुरक्षा बल के साथ कोई जहाज पर कैसे आ सकता है? अगर उन्हें कह दिया जाता तो वे खुद जहाज को किनारे पर लगा देते। बेहतर होता कि वहां उन्हें गिरफ्तार किए जाने की बात कह दी जाती।

लंदन की कोर्ट पहुंचा दुबई के शासक और पत्नी का झगड़ा

लंदन, एएफपी : दुबई के शासक की पत्नी ने बच्चों की देखभाल को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया है। लंदन की अदालत में सुनवाई शुरू हो गई है। यह सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी। शहजादी हया अपने पति शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम से अलग रह रही हैं। शहजादी के पति ने बच्चों को दुबई भेजे जाने की मांग की है।

ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मीडिया को इस मामले की रिपोर्टिंग की अनुमति दे दी। शहजादी हया जॉर्डन के दिवंगत शाह हुसैन की बेटी हैं। दोनों के बीच मामला दो बच्चों की देखभाल का है। शहजादी ने दुबई छोड़ दिया है। गौरतलब है कि शेख मोहम्मद और शहजादी हया के बीच टकराव दुबई के शाही परिवार के लिए मुसीबत का नया संकेत हो सकता है। पिछले साल शेख मोहम्मद की एक बेटी ने 40 मिनट का वीडियो जारी कर कहा था कि उन्हें जेल में डाल दिया गया था। इसके बाद उन्होंने दुबई से भागने की कोशिश की थी।

ब्रिटेन के नवागत पीएम बोरिस गर्लफ्रेंड कैरी संग पहुंचे प्रधानमंत्री आवास

- ब्रिटेन में बिनब्याहे जोड़े के 'फर्स्ट कपल' बनने का पहला मौका

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन में सोमवार को नवागत प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (55) अपनी गर्लफ्रेंड कैरी सीमंड्स (31) के साथ डाउनिंग स्ट्रीट स्थित सरकारी आवास में पहुंच गए। दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देशों में शुमार ब्रिटेन में यह पहला मौका है जब बिना शादी के कोई जोड़ा प्रधानमंत्री आवास में रहने पहुंचा है। प्रधानमंत्री आवास के प्रवक्ता ने दोनों के साथ रहने की पुष्टि की है।

बोरिस और कैरी का रिश्ता तो कई साल पुराना है लेकिन दोनों ने करीब डेढ़ साल पहले साथ रहना तब शुरू किया, जब बोरिस अपनी भारतीय मूल की पत्नी मरीना व्हीलर से अलग हो गए। दोनों का औपचारिक तलाक अभी नहीं हुआ है। हाल के दिनों में बोरिस और कैरी के संबंध तब चर्चा में आए जब साउथ लंदन स्थित कैरी के फ्लैट में देर रात पड़ोसियों ने बर्तन फेंके जाने और आपसी झगड़े की आवाजें सुनीं। इसके बाद उन्होंने पुलिस को फोन कर बुलाया। लेकिन पुलिस की पूछताछ में बोरिस और कैरी ने सब कुछ सामान्य बताया। इसके बाद बोरिस फ्लैट छोड़कर चले गए। कंजरवेटिव पार्टी में चुनाव अभियान के दौरान की यह घटना है। इसके कारण लोकप्रियता में आगे चल रहे बोरिस के भविष्य पर सवाल उठे थे। ...लेकिन अब वह चुनाव पार्टी का अंदरूनी चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बन चुके हैं और कैरी से उनके संबंध सामान्य हो चुके हैं। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास का नवागत जोड़ा एक कुत्ते को भी अपने साथ रखने की तैयारी में है।

प्रधानमंत्री आवास के प्रवक्ता ने साफ कर दिया है कि कैरी को केवल सरकारी आवास में रहने की सुविधा मिलेगी। उन्हें अन्य कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। उनकी सुविधाओं पर सरकारी खजाने से धन खर्च नहीं किया जाएगा। प्रथम महिला को मिलने वाला स्टाफ व अन्य सुविधाएं कैरी को नहीं मिलेंगी।

बोरिस जॉनसन। रायटर